AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बिहार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

ORIGINAL ARTICLE

Authors

पंकज कुमार गुप्ता
शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग
पटना विश्वविद्यालय
पटना, बिहार, भारत

डॉ. म. जमीलुर रहमान
पर्यवेक्षक
अर्थशास्त्र विभाग
बी. एन. कॉलेज
पटना, बिहार, भारत

शोध सार

बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 10.14 करोड़ थी। यहाँ की लगभग 58 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है तथा 61 प्रतिशत आबादी (15–19) आयु वर्ग की है। यह जनांकिकीय स्थिति भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि इस आबादी को कौशल युक्त बनाया जाए तो यह बिहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चुँकि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम हैं ऐसे में यहां रोजगार की सीधी संभावना बहुत कम है, परंतु यदि यहां की युवा आबादी को कौशलयुक्त बनाया जाए तो यह आबादी भारत के अन्य क्षेत्रों में या दुनिया के अन्य देशों में जाकर रोजगार हासिल कर सकती है। आंकड़ों से देखे तो पता चलता है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से बिहार के विकास दर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रही है। जबकि यहां औद्योगिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। स्पष्ट है सेवा क्षेत्र की भूमिका यहां सबसे अधिक रही है। व्यावसायिक शिक्षा में देखें तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विद्यालय स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय है बिहार के 38 जिलों में से मात्र 33 जिलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हुई लेकिन वर्तमान में इन 33 जिलों में से मात्र 14 जिले ऐसे हैं जहां व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई वाले स्कूलों में पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में 2018 – 20, 2019–21 तथा 2020–22 में एक भी छात्र नहीं मिले। ये जिले क्रमशः पूर्णिया, मुंगेर, जमुई, खगरीया, मधुबनी, गया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, बांका, सहरसा, बेगूसराय तथा गोपालगंज हैं बाकी 19 जिलों की बात करें तो पूरे बिहार में सत्र 2018–20 में कुल नामांकन 1210, सत्र 2019–2021 में 1082 तथा 2020–22 में 974 रहा है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति भी बहुत दयनीय है। ऐसे में बिहार के संपूर्ण युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना एवं कौशल युक्त बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है। बिहार के करीब आधे युवा जीवन–यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के शिक्षित और योग्य युवा निर्धन और निम्न शिक्षा स्तर वाले युवाओं की तुलना में अधिक बेरोजगार हैं। यहा सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत जिनके पास वर्ष में पूरे समय काम करने का अवसर नहीं मिलता।

कुल श्रमिकों के बीच काफी अधिक लगभग 38.5 प्रतिशत है जो काफी चिंता जनक है। यह भी देखा गया है कि लगभग 53 प्रतिशत श्रमिक खेतिहर मजदूर हैं और इनमें से कुल श्रमिकों के 74 प्रतिशत श्रमिक केवल कृषि कार्य में लगे हुए है। अतः राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में कृषि पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है तथा पर्याप्त कार्य बल को कौशल युक्त बनाने की जरूरत है ताकि उनका रोजगार के अन्य स्रोतों में समावेश हो सके।

मुख्य शब्द

कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, बिहार, रोजगार, आर्थिक विकास.

बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 10.14 करोड़ थी। यहाँ की लगभग 58 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है तथा 61 प्रतिशत आबादी (15–19) आयु वर्ग की है। यह जनांकिकीय स्थिति भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। बिहार में साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षता दर 73.39 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत है। 1999 – 2000 से 2005–06 के दौरान स्थिर कीमतों पर राज्य कि आय 5.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में बदलाव देखा गया और 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से राज्य की आर्थिक वृद्धि हुई। एक शानदार प्रदर्शन यह भी देखा गया की पहली अवधि की तुलना में अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल की गई विकास दर 2006–13 के दौरान न केवल बहुत अधिक रही बल्कि भारत के सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रही। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लगभग 10 करोड़ आबादी में 31 प्रतिशत आबादी 15 वर्ष से कम आयु की है तथा 61 प्रतिशत आबादी 15–59 वर्ष के कार्यशील आयु वर्ग की है। चूँकि कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या बड़ी है और अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत रोजगार है अतः इस जनसंख्या को राज्य के कार्य बल में शामिल होने की जरूरत है। यह महिलाओं और पुरुषों के बेहतर जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से पोषित एवं उत्पादक श्रम शक्ति एक गतिशील अर्थव्यवस्था और न्याय संगत समाज की दिशा में योगदान करती है जबकि रोजगार तक पहुंच का अभाव आत्म सम्मान को काम करता है और यह व्यक्ति और परिवार की बुनियादी जरूरतों को नकारते हुए सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। बिहार गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी मारझेल रहा है। बिहार के करीब आधे युवा जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के शिक्षित और योग्य युवा निर्धन और निम्न शिक्षा स्तर वाले युवाओं की तुलना में अधिक बेरोजगार हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत जिनके पास वर्ष में पूरे समय काम करने का अवसर नहीं मिलता। कुल श्रमिकों के बीच काफी अधिक लगभग 38. 5 प्रतिशत है जो काफी चिंता जनक है। यह भी देखा गया है कि लगभग 53 प्रतिशत श्रमिक खेतिहर मजदूर हैं और इनमें से कुल श्रमिकों के 74 प्रतिशत श्रमिक केवल कृषि कार्य में लगे हुए है। अतः राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में कृषि पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है तथा पर्याप्त कार्य बल को कौशल युक्त बनाने की जरूरत है ताकि उनका रोजगार के अन्य स्रोतों में समावेश हो सके।

क्रमांक	विभाग का नाम	योजना का नाम
1.	अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग	i) दशरथ मांझी कौशल विकास योजना (ii) एकीकृत थरूहट विकास योजना
2.	ग्रामीण विकास विभाग	(i) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ii) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (iii) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना
3.	श्रम संसाधन विकास	(i) कौशल विकास पहल योजना (ii) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

		(iii) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (iv) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना (v) कुशल युवा कार्यक्रम
4.	शहरी एवं आवास विकास विभाग	(i) कुशल विकास एवं प्लेसमेंट योजना
5.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	(i) मुख्य श्रम शक्ति योजना
6.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	(i) राज्य वित्त पोषित कौशल विकास कार्यक्रम
7.	समाज कल्याण विभाग	(i) मुख्यमंत्री शिक्षा वित्त योजना (ii) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
8.	शिक्षा विभाग	(i) हुनर (ii) व्यावसायिक शिक्षा कोर्स (iii) कम्युनिटी कॉलेज
9.	स्वास्थ्य विभाग	(i) आशा
10.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	ESDM, C-DAC, BSDM
11.	पर्यटन विभाग	(i) हुनर से रोजगार तक (के. यो.)
12.	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग	(i) प्रशिक्षण एवं विस्तार स्कीम योजना (ii) विशेष अवयव के लिए प्रशिक्षण योजना (iii) मत्स्य विस्तार योजना
13.	गृह विभाग	कैदियों के लिए प्रशिक्षण योजना
14.	कृषि विभाग	बीज ग्राम योजनाATMA, MIDH, बागवानी मिशन
15.	उद्योग विभाग	राज्य वित्त पोषित प्रशिक्षण योजना

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण

वर्तमान में बिहार सरकार के 15 विभाग कौशल विकास एजेंडा की दिशा में कार्य कर रहे हैं यह अपने–अपने दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न लक्ष्य समुहों के लिए विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इन विभागों द्वारा चलाई जा रही कौशल प्रशिक्षण योजनाएं इस प्रकार हैं:

इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्र के 17 विभागों द्वारा स्वचालित विभिन्न योजनाएं भी राज्य के विभिन्न जिलो में संचालित हो रही है। एक बड़ी योजना विद्यार्थियों के कौशल विकास की है जिसके जरिए विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाया जाता है लेकिन बिहार इन योजनाओं के लाभ उठाने में 12वे स्थान पर है। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में बिहार में कौशल विकास केंद्र और पाठ्यक्रमों के प्रति उदासीनता रही है। AUGC ने करियर ओरिएंटेड कोर्स की शुरुआत की जिसमें दर्जनों पाठ्यक्रम है लेकिन बिहार में अब तक सिर्फ 15 पाठ्यक्रमों की शुरुआत हो सकी है। कॉलेज और विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा स्तर बढ़ने के लिए यूजीसी वित्तीय सहायता भी देता है। बिहार के संस्थान चाहते तो इनका लाभ उठा सकते थे लेकिन योजनाओं का लाभ उठा पाने में राज्य के संस्थान सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले जब यूजीसी ने आवेदन मंगाया था तो बिहार के 38 संस्थानो ने आवेदन दिया था लेकिन बिहार के किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज ने कौशल विकास की शिक्षा देने के योग्य नहीं माना गया था।

विद्यालय स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

बिहार में विद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इंटरमीडिएट स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा कोर्स प्रारंभ किए गए जिसके लिए बिहार के प्रत्येक जिले के कुछ चुने हुए विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तरीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इसके लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षक की भी बहाल किए गये, परंतु इसके शिक्षा की

मुख्य धारा में शामिल नहीं होने के कारण इसकी प्रगति नहीं हो सकी तथा यह व्यवस्था लगभग मृतप्रायः ही रही। बिहार के एक दैनिक समाचार पत्र 'आज' में 'स्कूलों में बढ़ रही व्यावसायिक शिक्षा' नामक एक लेख में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अनुसार, राज्य में पिछले 6 वर्षों यानी तीन शैक्षणिक सत्रों में इंटरमीडियट स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं के संख्या घटती चली गई।

प्रदेश में प्लस टू की पढ़ाई वाले पुराने 148 विद्यालयों में 2 वर्षीय इंटरमीडिएट ऑस्ट्रेलिया व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू हुई थी पढ़ाई के लिए हर विद्यालय में तीन–तीन ट्रेड दिए गए थे। छात्र–छात्राओं के दाखिले के लिए हर ट्रेड में 25 सीट तय की गई पढाने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी हर विद्यालय के हर ट्रेड में एक–एक अनुदेशक पदस्थापित किए गए प्रयोगशाला सहायकों का भी के बाद बिहार में व्यावसायिक क्षेत्र की पढ़ाई वाले 148 विद्यालय में से 91 विद्यालय बच गए थे, विद्यालय 33 जिलों में है इनमें भागलपुर, पूर्णिया, जहानाबाद, मुंगेर, दरभंगा, जमुई, क्रिया, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, नवादा, नालंदा, रोहतास एरिया, मधुबनी, कटिहार, गया, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, बांका, सहरसा, सरण, किशनगंज, पटना, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं सिवान शामिल है बाद में इन स्कूलों में प्रत्येक ट्रेड में सीटों की संख्या दूनी की गई। संबंधित 91 विद्यालयों में 108 अनुदेशक तथा 120 प्रयोगशाला सहायक कार्यरत है उनके वेतन आदि पर प्रतिमाह 2.28 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं,

बावजूद व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं की संख्या घटती चली गई है स्थिति की अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शैक्षिक सत्र 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम वाले छात्र–छात्राओं की संख्या 1210 थी जो शैक्षिक छात्र 2019–21 में हटकर 1082 पहुंच गई, इस संख्या में और गिरावट आ रही है। शैक्षिक सत्र 2020 में सहायक पाठ्यक्रम पढ़ने वाला छात्र–छात्राओं की संख्या 974 पहुंच गई है सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई वाले 33 जिलों में 14 जिले ऐसे हैं जहां व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई वाले स्कूलों में पिछले तीन शैक्षिक क्षेत्र में 2018–20 2019–21 तथा 2020–22 में एक भी छात्र–छात्र नहीं मिले हैं। पूर्णिया, मुंगेर, जमुई, क्रिया, एरिया, मधुबनी, गया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, बांका, सहरसा, बेगूसराय और गोपालगंज शामिल है बाकी 19 जिलों बात करें तो निम्न तालिका में इसकी स्थिति देख ले।

बिहार में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति जिलावार कुल नामांकन

क्र. सं.	जिला का नाम	छात्रों की संख्या (कुल नामंकन)		
		2018–20	2019–21	2020–22
01.	भागलपुर	122	110	15
02.	जाहानाबाद	47	18	43
03.	दरभांगा	73	71	93
04.	औरंगाबाद	17	28	22
05.	समस्तीपुर	42	31	44
06.	पूं चंपारण	30	35	22
07.	नवादा	56	48	42
08.	नालंदा	58	55	37
09.	रोहतास	145	92	50
10.	कटिहार	35	38	48
11.	वैशाली	10	10	03
12.	सीतामढी	53	58	58
13.	सारण	41	26	43
14.	किशनगंज	00	00	04

15.	पटना	175	193	204
16.	भोजपुर	89	56	58
17.	बक्सर	16	20	22
18.	मुजफ्फरपुर	183	180	172
19.	सीवन	18	13	07
	कुल	1210	1082	974

(स्त्रोतः दैनिक समाचार पत्र आज, दिनांक 16 मई, 2022, पृष्ठ 1,9)

इसके अतिरिक्त कौशल विकास हेतु सरकार लाइन अनेक नीतिगत एवं संस्थान प्रयास किए गए हैं जिसके तहत राज्य के लगभग सभी जिलों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि खोले गए हैं। फसल विकास निगम की स्थापना की गई है जिसके द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन की श्रम शक्ति को बताती राज्य के युवाओं अचानक कुशलताओं का मिशन शुरू किया जा सके, बाद में इस श्रम संस्थान विभाग के अधीन कर दिया गया। नवंबर 2016 में राज्य सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया गया यह राज्य सरकार के सभी 534 संचालित है कौशल संवाद कौशल तथा बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान शिक्षा दी जाती है साथ ही डोमेन स्केल के कारण 16 विभिन्न रोजगार क्षेत्र में कौशल परीक्षित प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य भर में 1700 से अधिक कुशल युवा केंद्र तथा 1200 से अधिक डोमेन स्केलिंग केंद्र कार्यरत है जो अब तक लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं कई हजार युवाओं को रोजगार एवं स्वयं रोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि कौशल विकास के क्षेत्र में बिहार के पिछले दशक की तुलना में काफी प्रगति की है आधारभूत ज्ञान के स्तर पर कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य की प्रगति संतोषजनक है परंतु उच्च स्तरीय ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य अभी भी काफी पीछे है। इस हेतु एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. सिंह, रमेश (2016) *बिहार में रोजगार की स्थिति एवं कौशल विकास,* आनन्द पब्लिसिंग हाउस पटना 2015, पृ. 53।
2. दैनिक समाचार पत्र, आज, पटना, सोमवार, 16 मई 2022 पृ. 1–9, स्कूलो में पिछड़ रही व्यावसायिक शिक्षा।
3. NSSO (2015) शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर 68 वें दौर की रिपोर्ट, 22 सितंबर 2015।
4. Skill Development In Bihar, Vision and Strategy, (2016), https://skillmissionbihar.org/user/pages/files/policy-documents/Skill_Development_in_Bihar-Vision__Strategy.pdf, Assecced on 12/02/2025.

——==00==——